



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार



अशोक गहलोट, मुख्यमंत्री, राजस्थान

दो वर्ष जन सेवा के

मुख्यमंत्री को सीधे करें ईमेल
writetocm@rajasthan.gov.in

समस्या समाधान हेतु हेल्पलाइन
181

किसान

- सहकारी बैंकों के 20.85 लाख किसानों के 14 हजार करोड़ रुपये के फसली ऋण माफ। इस ऋण माफी में पिछली सरकार के बकाया 6 हजार करोड़ रुपये भी शामिल हैं।
- सहकारी बैंकों के 61 लाख ऋणी इकाइयों को 19,323 करोड़ रु. के ब्याज मुफ्त फसली ऋण वितरित-12.67 लाख नये किसान भी शामिल।
- 2022 तक पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से दिन में मिलेगी तीन फेज कृषि बिजली। अभी राज्य के 15 जिलों में यह योजना शुरू।
- कृषि जिन्सों की बेहतर विपणन व्यवस्था के लिए 643 ग्राम सेवा/क्रय-विक्रय सहकारी समितियों एवं राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के भण्डारगृहों को निजी गौण मण्डियों का दर्जा दिया।
- राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति - 2019 : किसानों को पूंजी एवं ब्याज लागत पर 2 करोड़ रुपये तक का अनुदान। सुगम ऋण हेतु 500 करोड़ रुपये के कोष का सृजन।
- कृषक कल्याण कोष : 2,000 करोड़ रुपये का कोष सृजित।
- दो वर्षों में किसानों के बिजली बिलों में 27,229 करोड़ एवं घरेलू उपभोक्ताओं को 968 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की। पूरे 5 वर्ष कृषि हेतु बिजली की दरें नहीं बढ़ाने का निर्णय। 1 लाख 61 हजार नये

विद्युत कनेक्शन कृषि हेतु जारी।

- “राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम-2019” जारी। 2 लाख 80 हजार किसान लाभान्वित।
- पशुधन हेतु उपयोगी दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध, 567 लाख पशुओं का उपचार व 786 लाख पशुओं का टीकाकरण।
- गौशालाओं को 822 करोड़ रु. की सहायता। पशुपालक किसानों के लिए दूध संकलन पर 2 रु. प्रति लीटर अनुदान।

स्वास्थ्य सेवाएं एवं कोरोना प्रबंधन

- शानदार कोरोना प्रबंधन से राजस्थान बना मॉडल। सभी जिलों के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच व इलाज। हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को दी मजबूती। ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन प्लांट्स में बड़े पैमाने पर वृद्धि।
- राजस्थान देश में पहला राज्य है, जहां संविदा/ मानदेय कर्मियों सहित सभी कर्मचारियों को कोरोना ड्यूटी के दौरान कोरोना से मृत्यु होने पर आश्रितों को 50 लाख की सहायता।
- पोस्ट कोविड लक्षण जैसे थकावट, सांस फूलना, याददाश्त में कमी, शुगर बढ़ जाना, स्ट्रेस-डिप्रेशन-एंग्जाइटी, पुरानी बीमारी का बढ़ जाना जैसी स्थिति होने पर तुरंत पोस्ट कोविड क्लिनिक/डॉक्टर से सम्पर्क करें।
- कोरोना टीकाकरण के लिए प्रदेश सरकार की हर स्तर पर पूरी तैयारी है, जैसे ही

वैक्सीन आयेगी राज्य सरकार प्रभावी वैक्सीनेशन प्रबंधन सुनिश्चित करेगी।

- कोविड के कारण विद्युत बिलों के संबंध में 1.05 करोड़ घरेलू एवं 14.50 लाख कृषि सहित अन्य उपभोक्ताओं को दी गई बिल जमा कराने की अवधि में छूट के कारण 310 करोड़ का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया।
- लॉकडाउन में 33 लाख जरूरतमंद परिवारों को 3,500 रुपये प्रति परिवार की दर से 1,144 करोड़ रु. की सहायता।
- 713 दवाइयां व 90 जांचें निःशुल्क। कैंसर, हृदय, सांस और गुर्दा रोग जैसी गंभीर बीमारियों की दवा भी निःशुल्क। 20 उपजिला व 21 जिला अस्पतालों में सेन्ट्रलाइज्ड ऑक्सीजन पाइपलाइन।
- भामाशाह योजना के स्थान पर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू। इसमें 10 लाख नये परिवार जोड़कर कुल 1.10 करोड़ परिवारों को अब 3 लाख की बजाय 5 लाख का निःशुल्क बीमा।
- हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के लक्ष्य के तहत 15 और जिलों में नये मेडिकल कॉलेज स्वीकृत, अब 33 में से 30 जिलों में 31 सरकारी मेडिकल कॉलेज होंगे।

उद्योग

- एमएसएमई उद्योग लगाने पर तीन साल तक किसी अनुमति एवं निरीक्षण से मुक्ति का कानून बनाया।
- उद्योगों से जुड़ी समस्याओं के समाधान

के लिए 'वन स्टॉप शॉप' व्यवस्था।

- पंचपदरा (बाड़मेर) में 43 हजार करोड़ लागत की रिफाइनरी परियोजना एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लैक्स का कार्य तेज गति से जारी।
- राजस्थान सौर ऊर्जा नीति - 2019 तथा राजस्थान पवन एवं हाईब्रिड ऊर्जा नीति - 2019: पर्यावरण संरक्षण, निवेश और रोजगार की दिशा में बड़ा कदम।

आधारभूत ढांचा

- प्रदेश में सड़क विकास पर 10,579 करोड़ रु. व्यय कर 24,100 किलोमीटर सड़क निर्माण। जिसमें 1650 करोड़ रु. से 3923 किलोमीटर नई सड़कें शामिल।
- प्रदेश में प्रथम भूमिगत मेट्रो रेल सेवा जयपुर में शुरू।
- 9 वृहद पेयजल परियोजनाओं से 5 हजार गांवों एवं 14 शहरों को (आंशिक) सतही स्रोत से शुद्ध पेयजल आपूर्ति।

ग्रामीण विकास

- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 5 लाख आवास निर्मित। जिस पर 5,410 करोड़ रु. व्यय। सर्वाधिक आवास बनाने पर राज्य को प्रथम पुरस्कार।
- 57 नई पंचायत समितियां बनायीं।
- मनरेगा में 99.82% मजदूरी का भुगतान 15 दिन में करना सुनिश्चित किया।

रोजगार

- 79,671 युवाओं को सरकारी नौकरियां दीं। न्यायालय में अटकी भर्तियों की

प्रभावी पैरवी कर 25 हजार युवाओं को नियुक्ति दी। प्रक्रियाधीन भर्तियों में आ रही बाधाओं के समाधान के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध।

- अप्रैल, 2021 में 31 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए होगा रीट का आयोजन।
- विशेष योग्यजन को सरकारी सेवाओं में आरक्षण 3 से बढ़ाकर 4 प्रतिशत।
- EWS आरक्षण में शामिल लोगों के लिए अचल सम्पत्ति की शर्त हटाकर 8 लाख वार्षिक आय को एकमात्र आधार बनाया।
- पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न आधार पर डीएसपी रैंक तक की नौकरियां दी।

शिक्षा

- सभी बालक/बालिकाओं को बेहतर शिक्षा के लिए 201 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) खोले, जिनमें 68,540 विद्यार्थी नामांकित।
- 90 नये राजकीय महाविद्यालय खोले।

सामाजिक सुरक्षा

- इंदिरा रसोई योजना - प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में जरूरतमंदों को 8 रुपये में भोजन की व्यवस्था। अब तक 1 करोड़ 12 लाख भोजन थाली उपलब्ध कराई। सरकार द्वारा 12 रुपये प्रति थाली अनुदान।
- वृद्धों, विधवाओं और एकल महिलाओं के लिए पेंशन वृद्धि।

- सिलिकोसिस नीति-2019 में पीड़ित व्यक्ति एवं उसके परिवार को पुनर्वास के लिए 5 लाख रुपये की सहायता। प्रति माह रु. 1,500 की पेंशन।

- इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना : चार जनजाति जिलों में द्वितीय संतान के समय प्रत्येक गर्भवती व धात्री महिला को रु. 6,000 की वित्तीय सहायता।

सुशासन

- जन कल्याण पोर्टल शुरू - जहां सभी सरकारी योजनाओं में पात्रता, शर्तें, लाभ, सरकार की उपलब्धियां/नवाचार एवं परिपत्र/आदेश उपलब्ध।
- जन सूचना पोर्टल पर सभी योजनाओं के लाभार्थियों की जानकारी उपलब्ध।
- 80 हजार ई-मित्र कियोस्क पर आमजन को उनके घर के नजदीक 450 सेवाएं उपलब्ध।
- थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होने पर देश में पहली बार पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पंजीकरण व्यवस्था। एफआईआर दर्ज करने को अनिवार्य बनाने से धारा 156(3) के तहत कोर्ट से दर्ज होने वाली एफआईआर में सारभूत कमी।
- प्रत्येक पुलिस जिले में महिला अपराधों के लिये विशेष जांच इकाई बनाई। डीवाईएसपी रैंक के अधिकारी का पदस्थापन। आगन्तुकों के लिये थानों में स्वागत कक्ष स्थापित।
- एंटी करप्शन ब्यूरो को मजबूत किया एवं शिकायत के लिये 1064 हेल्पलाइन शुरू।